शोध संचयन
SHODH SANCHAYAN
ISSN 2249-9180 (Online)
ISSN 0975-1254 (Print)
RNI No.: DELBIL/2010/31292

Bilingual journal of Humanities & Social Sciences

Half Yearly

Vol-1, Year-1,

15 Jan-2010

उच्च शिक्षा और शोधः परिवर्तन की पहल में धींगामुश्ती

डॉ. रमेश वर्मा

*वरिष्ठ पत्रकार, रीडर, हिन्दी विभाग, डी०ए-वी० कॉलेज, कानपुर

www.shodh.net

उच्च शिक्षा और शोधः परिवर्तन की पहल में धींगामुश्ती

- डॉ. रमेश वर्मा

भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने प्राइमरी से उच्च शिक्षा तक आमूल चूल परिवर्तन का वीणा उठाया है। इस दिशा में उन्होंने कई अहम् कदम उठाये जैसे - अनिवार्य व निशुल्क शिक्षा, समान पाठ्यक्रम, कक्षा-प्रोन्नति, कोडिंग सिस्टम आदि। इसे लेकर शिक्षाविदों व राजनयिकों में जबर्दस्त प्रतिक्रिया हुई। ये कदम कितने सार्थक व उपयोगी है, समय की कसौटी पर कितने खरे उतरेंगे, भूमंडलीकरण के दौर में कहाँ तक अस्तित्व बरकरार रख सकेंगे, इस बारे में फिलहाल अपने-अपने ढंग से प्रबल संभावनायें व्यक्त की जा रही हैं।

मानवसंसाधन विकास मंत्री, कपिल सिब्बल का सबसे ज्यादा जोर उच्च शिक्षा पर है। उनका मानना है कि राष्ट्र विकास के लिए उच्च शिक्षा का मजबूत होना परम् आवश्यक है।

प्रसिद्ध चिंतक और विधिवेत्ता नानी पालकीवाला का शिक्षा की महत्ता के विषय में कहना है -

''शिक्षा एक शिला है, जिस पर भारत को अपनी राजनैतिक रक्षा का निर्माण करना है। हमारे देश का निर्माण ईटों के द्वारा नही वरन् मस्तिष्क द्वारा, सीमेंट की सहायता से नही बल्कि ज्ञान की सहायता से होगा। अगर हम शिक्षा ग्रहण करने का कष्ट नहीं उठा सकते तो सभ्य समाज में बने रहने का कष्ट भी नहीं उठा पायेंगे।''

वर्तमान में जनसंख्या का वह भाग, जो उच्च शिक्षा में प्रवेश करता है, मात्र 7 प्रतिशत है। हमारी जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग को उच्चशिक्षा की सुविधा प्राप्त नहीं है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उच्च शिक्षा पर अपनी आख्या में यह उल्लेख किया है कि भारत जैसे देश में, जिसमें 100 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं, में विश्वविद्यालयों की संख्या बहुत कम है। नामांकन अनुपात में लगभग 15 प्रतिशत बृद्धि के लिए ज्ञान आयोग के अनुसार, वर्ष 2015 तक भारत में 1500 विश्वविद्यालय होने चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि विश्वविद्यालयों की संख्या 5 गुना बढ़ानी होगी।

सवाल यह है कि क्या विश्वविद्यालयों की संख्या 5 गुना बढ़ाने मात्र से हम विश्व की प्रतिस्पर्द्धा में आ जायेंगे। विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के ढर्रे से तो कदापि प्रतीत नही होता है। सन् 2006 में टाइम्स हायर एजुकेशनल सप्लीमेंट ने विश्व के 100 चोटी के विश्वविद्यालयों की जो रैंकिंग की, उनमें भारत की एकमात्र आई0आई0टी0, खड़गपुर का नाम था। मैकिन्जी रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर वर्ष पास होकर निकलने वाले छह लाख इंजीनियरों में से 75 प्रतिशत ऐसे होते हैं, जो कि अतिरिक्त ऑन-दॅ-जॉब ट्रेनिंग के बिना ठीक-ठाक ढंग से काम नहीं कर सकते। उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक के अनुसार ''भारत में आवश्यकत कुल संख्या के 35 प्रतिशत छात्र ही एम0बी0ए0 डिग्री प्राप्त करते हैं। इनमें 8-9 प्रतिशत ही नौकरी करने लायक होते हैं।'' प्रोफेसर पाठक ने यह दावा जुलाई 2008 में ए.बी.सी. चैनल के आनॅलाइन साक्षात्कार में किया है।

यह दशा तो तकनीकी व प्रबंधकीय संस्थाओं की है, जिन विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में परम्परागत विषयों का पठन-पाठन होता है वहाँ तो स्नातक रोजगार शून्य है। स्वतंत्रता के 60 वर्षों में विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों की ओर छात्र-छात्राओं का रूझान बढ़ा है किन्तु उच्च शिक्षा की गुणवत्ता आशानुरूप न होने से ज्ञान-विज्ञान, साहित्य, मानविकी विषयों आदि में उपलब्धि नगण्य है। लगभग ऐसी ही दशा शोध क्षेत्र में है। शोध मौलिकता, सामाजिक व बौद्धिक रूप से प्रासंगिकता और प्रेरणा से कोसों दूर है। जबकि छात्र-छात्राओं के समक्ष नित-नूतन चुनौतियाँ खड़ी हो रही है। उ.प्र. के राज्यपाल बी0एल0 जोशी ने 5 जनवरी 2010 को छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षांत समारोह के अध्यक्षीय भाषण में कहा कि ''नव प्रौद्योगिकी और सूचना संजाल के तीव्र विकास के कारण विद्यार्थियों को अपने कार्य-परिवेश में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दो दशकों में पूरे विश्व में नैनो तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर विज्ञान, सूचना एवं जन संचार तकनीक के क्षेत्र में असाधारण प्रगति हुई है। उनके विस्तार में व्यावहारिक रूप से मानव जाति के प्रयास, अन्तरिक्ष विज्ञान तथा आनुवांशिकी से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा माइक्रोचिप्स तक सभी समाहित हैं। अगले 10 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में इन्टरनेट सुविधा का विशाल विस्तार दृष्टिगोचर होगा। इसके फलस्वरूप होने वाली संयोजन क्षमता में बृद्धि से जन साधारण के कार्य करने के तरीके में कई परिवर्तन आएंगे। इसके कारण कारोबारी कीमतों में भारी कमी तथा कार्य क्षमता में तदनुसार बृद्धि होना तय है।''

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता के लिये विश्वविद्यालयों-महाविद्यालयों की रैंकिंग में 'नैक', शिक्षकों की प्रोन्नति में सेमिनार, शोधपत्र, माइनर-मेजर प्रोजेक्ट, शोध में प्रवेश परीक्षा, गहन परीक्षण जैसी व्यवस्थायें लागू की है। आयोग की इन व्यवस्थाओं से उच्च शिक्षा की उत्कृष्टता में कितना और कब सुधार होगा, यह तो समय बताएगा। व्यावहारिक दृष्टिकोण से विश्वविद्यालयों - महाविद्यालयों में रैंकिंग 'ए' पाने के लिए होड़ है। प्राचार्यों, शिक्षकों व छात्र-छात्राओं का अधिकतर समय 'नैक' की खाना-पूरी करने के लिए साज-सज्जा, दिखावट, सेमिनार,

शोध संचयन
SHODH SANCHAYAN
ISSN 2249-9180 (Online)
ISSN 0975-1254 (Print)
RNI No.: DELBIL/2010/31292

Bilingual journal of Humanities & Social Sciences

Half Yearly

Vol-1, Year-1,

15 Jan-2010

उच्च शिक्षा और शोधः परिवर्तन की पहल में धींगामुश्ती

डॉ. रमेश वर्मा

*वरिष्ठ पत्रकार, रीडर, हिन्दी विभाग, डी०ए०वी० कॉलेज, कानपुर

www.shodh.net

संगोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल-कूद, अभिभावक-शिक्षक सम्मेलन, पूर्व छात्र सम्मेलन, विभिन्न समितियों की कार्यवाहियों, शिक्षकों की उपलब्धियों को सजाने-संवारने आदि में व्यतीत हो रहा है। 'नैक' 5 वर्ष में एक बार होता है, इसलिए एक 'नैक' से विश्वविद्यालय-महाविद्यालय साँस भी नही ले पाते हैं कि प्रबन्ध तंत्र के दबाव में दूसरे 'नैक' की मशक्कत होने लगती है। 'नैक' वाले वर्ष में तो पूरा शिक्षा सत्र ऐसे ही आयोजनों से गुजर जाता है।

शिक्षकों में प्रोन्नति मानकों को लेकर चिंता सताये रहती है। प्रोन्नति के नम्बरों की गणना शोध पत्र, सेमिनार, प्रोजेक्ट जैसे कार्यों से होने लगी है। इसलिए शिक्षकों में शोध पत्रों के प्रकाशन, सेमिनारों व संगोष्ठियों के भागीदारी का प्रमाण पत्र पाने, प्रोजेक्ट स्वीकृत कराने की मारा-मारी रहती है। कुछ लोगों ने इसका व्यापारिक लाभ उठाना प्रारम्भ कर दिया है। शोध पत्रिकाओं की भरमार हो गई है। शोध पत्रिका की सदस्यता के नाम पर हजारों वसूल करके शोधपत्र प्रकाशित किए जा रहे हैं। सेमिनार, संगोष्ठी की भागीदारी का पंजीयन शुल्क हजारों में कर दिया गया है। सेमिनार में शोध पत्रों के नाम पर लेख पढ़े जा रहे है। इन लेखों से सेमिनार संयोजक पुस्तकें छपवाने लगे है। शोध का नया अध्यादेश अभी अधिकतर विश्वविद्यालयों में लागू भी नही हुआ है किन्तु चोर दरवाजे खोले जाने लगे हैं।

यह कहने का कतई तात्पर्य नही है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षा को उत्कृष्ट बनाने के फैसले पूरी तरह गलत हैं किन्तु अंधी दौड़ के प्रति तो सजग होना ही पड़ेगा। पहला प्रयास यही होना चाहिए कि विश्वविद्यालयों-महाविद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति मानक के अनुरूप 75 प्रतिशत हो, शिक्षक अनिवार्य रूप से पढ़ाए, इसके लिए उच्च स्तर पर निगरानी की जानी चाहिए, अकादामिक स्वायत्तता का ऐसा मॉडल विकसित होना चाहिए जिसमें नौकरशाहों व राजनीतिज्ञों का हस्तक्षेप न हो।

शोध संचयन
SHODH SANCHAYAN